



## दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने के लिए महापंचायत का आयोजन

सवेरा न्यूज, कास.

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर : राजधानी दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली की 360 पंचायतों ने एक साथ मिलकर महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली के नोटीफाइड अर्बनाइजेबल जोन में अप्रोडेबल हाउसिंग का सपना साकार करने के उद्देश्य से जमीन खरीदने वाली संस्था मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स ने भी हिस्सा लिया। साथ ही महापंचायत में वर्षों से अपने घर का सपना साकार का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने सरकार से मांग करते हुए



जानकारी देते मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी के लोग

कहा, किसानों के हित में संशोधित लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को अविलंब लागू किया जाय। साथ ही जिन गावों में किसानों की जो जमीन है उस पर उन्हें निशुल्क मालिकाना हक दिया जाय।

कार्यक्रम में मौजूद मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स के सदस्य केएस कृष्णन

ने कहा, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान 2001-2021 में अनुमान जताया गया था कि 2021 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच जायेगी। इस अनुमानित आबादी को मकान मुहैया कराने के लिए ही साल 2013 में पिब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर लैंड

पूलिंग पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इस नीति में डीडीए को भूमि अधिग्रहण से दूर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली एजेंसी के तौर पर निर्धारित किया गया था। तब अनेक संस्थाओं ने सोसायटियां बनाकर किसानों से जमीन खरीदी लेकिन इससे पहले कि सोसायटियां और उनके सदस्य अपने आशियाने का सपना पूरा कर पाते साल 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी में कई तरह के बदलाव कर दिये गए जिससे न सिर्फ सोसायटियों के सदस्यों बल्कि जमीन बेचने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जाय जिससे लोगों के आशियाने का सपना पूरा हो सके।

DELHI-NCR SAVERA Edition  
Oct 3, 2023 Page No. 11  
Powered by : eReleGo.com



है। पिछले 500 जीबी डेटा भी मिला है। जिसमें ईएसआईएस इराक एंड में वांछित की संदिग्धों प्राथ ही तीन रखा था। ना देने वाले डी जाएगी। नैपटॉप और हैं। साथ ही

500 जीबी डेटा भी मिला है। जिसमें वम बनाने के यूट्यूब वीडियो के लिंक और विभिन्न स्थानों की गूगल से ली गई तस्वीरें हैं। जांच के दौरान यह पता चला कि एक विदेशी-आधारित हैंडलर ने संभवतः फरवरी में आतंकी हमले को अंजाम देने के निर्देश के साथ शाहनवाज को इमरान और यूनुस के संपर्क में रखा था। 10-15 दिनों के बाद शाहनवाज कथित तौर पर रिजवान को दिल्ली लाया गया।



नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके से आज सुबह आईएसआईएस के सदस्य आतंकी शाहनवाज उर्फ शौफी उज्जमा को गिरफ्तार किया गया। शाहनवाज की गिरफ्तारी भी स्पेशल सेल की तरफ से की गई। शाहनवाज पेशे से इंजीनियर है। वह पुणे के आईएसआईएस से जुड़े एक केस में शामिल हैं। पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद से दिल्ली में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। उसने माइनिंग इंजीनियरिंग की है। उसे ब्लास्ट करने की जानकारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अरशद वारसी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अरशद वारसी भी झारखंड का ही रहने वाला है।

उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अरशद फिलहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है। अरशद लगातार आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में था। वह उनके साथ रेगुलर रिपोर्ट शेयर कर रहा था। मोहम्मद रिजवान अशरफ ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। रिजवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। रिजवान ने मौलवी के रूप में भी ट्रेनिंग ली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कमिश्नर एचजीएस घालीवाल ने बताया कि इन तीनों की गिरफ्तारी से आईएसआईएस के पैर इंडिया मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। घालीवाल ने बताया कि इन लोगों का उद्देश्य जाने-माने लोगों को निशाना बनाना था।

## टी के बने

ख सिंह की उल्लान को जागो का वार को दल र्थकों तथा एरा श्री गुरु 1-1 पहाड़ी श्रवण करके जलथा तथा गालों के रागी गी का गायन गो के प्रधान गाल सिंह ने नजीत सिंह ल के लिए स्ताव रखा। रा मंजूरी दी वत होने पर हुए जीके ने इथा भारत-कर अपने पर श्री गुरु वर्ष पूरे होने गों के द्वारा

## दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने की डीडीए से मांग

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संशोधित लैंड पॉलिसी लागू करवाने के लिए दिल्ली के किसानों का विरोध जारी है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली के नोटीफाइड अर्बनाइजेबल जोन में अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना साकार करने के उद्देश्य से जमीन खरीदने वाली संस्था मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी एंड लैंड ओनर्स भी किसानों के साथ है। मौजूद मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी एंड लैंड ओनर्स के सदस्य केएस कृष्णन ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान 2001-2021 में अनुमान जताया गया था कि 2021 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस अनुमानित आबादी को मकान मुहैया कराने के लिए ही साल 2013 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप



(पीपीपी) आधार पर लैंड पूलिंग पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। इस नीति में डीडीए को भूमि अधिग्रहण से दूर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली एजेंसी के तौर निर्धारित किया गया था। तब अनेक संस्थाओं ने सोसायटियों बनाकर किसानों से जमीन खरीदी लेकिन इससे पहले कि सोसायटियां और उनके सदस्य अपने आशियाने का सपना पूरा कर पाते साल 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी में कई तरह के

बदलाव कर दिये गए जिससे न सिर्फ सोसायटियों के सदस्यों बल्कि जमीन बेचने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी एंड लैंड ओनर्स के सचिव वीके शर्मा ने कहा कि 2018 की पॉलिसी में प्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 400 से घटाकर 200 कर दिया गया इससे सोसायटियों के टावरों में बनने वाले मकानों की संख्या में कमी होगी।

## यानगरी के सितारे



## सफदरजंग में मरीजों की सुविधा में बड़ा बदलाव

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में उपचार रहे मरीजों को मंगलवार से 11:30 तक ओपीडी की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में अभी मंगलवार 11:30 बजे तक ओपीडी की

मिलने पर इन्हें रातभर अस्पताल परिसर में ही रहना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए पुराने कोविड सेंटर में सुविधा शुरू की गई है। इस केंद्र पर दोपहर बाद से पच्ची बनने लगेगी। सफदरजंग अस्पताल भी एम्स की तर्ज पर रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी जांच की



क्या आप कोल  
लेकिन कल  
पढ़ने के लिए  
दैनिक भास्कर पर

# दैनिक भास्कर

देश का विश्वस्तरीय अखबार

बीकानेर | 05-14, 2019-10-4 | 02 अक्टूबर 2021 | पृष्ठ सं. 20 | शुल्क 3.00

वेब संस्करण

dainikbhaskarup.com

इंदाजी, नोएडा, लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित



## दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने के लिए महापंचायत का आयोजन

### भास्कर समाचार सेवा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने के लिए जंतर मंतर पर रविवार को दिल्ली की 360 पंचायतों ने एक साथ मिलकर महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली के नोटीफाइड अर्बनाइजेबल जोन में अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना साकार करने के उद्देश्य से जमीन खरीदने वाली संस्था मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स ने भी हिस्सा लिया। साथ ही महापंचायत में वर्षों से अपने घर का सपना साकार का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने सरकार से मांग करते हुए कहा, किसानों



के हित में संशोधित लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को अविलंब लागू किया जाय। साथ ही जिन गावों में किसानों की जो जमीन है उस पर उन्हें निशुल्क मालिकाना हक दिया जाय। कार्यक्रम में मौजूद मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स के सदस्य केएस कृष्णन ने कहा दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान 2001-2021 में अनुमान जताया गया था कि 2021 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच जायेगी।

मांग

जंतर मंतर पर महापंचायत का हुआ आयोजन

## संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी की जाए शीघ्र लागू

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (देशबन्धु)। राजधानी दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने के लिए जंतर-मंतर पर रविवार को दिल्ली की 360 पंचायतों ने एक साथ मिलकर महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली के नोटिफाइड अर्बनाइजेबल जोन में अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना साकार करने के उद्देश्य से जमीन खरीदने वाली संस्था मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स ने भी हिस्सा लिया।

साथ ही महापंचायत में वर्षों से अपने घर का सपना साकार का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों के हित में संशोधित लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को अविलंब लागू किया जाय। साथ ही जिन गावों में किसानों की जो जमीन है उस पर उन्हें निशुल्क मालिकाना हक दिया जाय। कार्यक्रम में मौजूद मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स के सदस्य



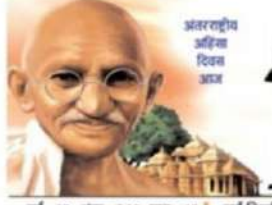
■ वर्षों से घर का सपना साकार का इंतजार कर रहे लोगों व किसानों के हितों को लेकर की चर्चा

केएस कृष्णन ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान 2001-2021 में अनुमान जताया गया था कि 2021 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस अनुमानित आबादी को मकान मुहैया कराने के लिए ही साल 2013 में

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर लैंड पूलिंग पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इस नीति में जीडीए को भूमि अधिग्रहण से दूर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली एजेंसी के तौर पर निर्धारित किया गया था। तब अनेक संस्थाओं ने सोसायटियां बनाकर

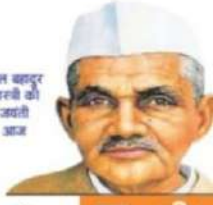
किसानों से जमीन खरीदी लेकिन इससे पहले कि सोसायटियां और उनके सदस्य अपने आशियाने का सपना पूरा कर पाते साल 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी में कई तरह के बदलाव कर दिए गए जिससे न सिर्फ सोसायटियों के सदस्यों बल्कि जमीन बेचने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

यही वजह है कि हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की जाए जिससे लोगों के आशियाने का सपना पूरा हो सके।



# विराट वैभव

राष्ट्रीय अखबार - खोले वैभव के द्वार



वर्ष : 18, अंक : 240, पृष्ठ : 16

नई दिल्ली, सोमवार, 02 अक्टूबर 2023

दिल्ली-जयपुर से प्रकाशित

facebook.com/viraatvaibhavdelhi

epaper.viraatvaibhav.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VVpaper

मूल्य :- ₹ 3/-

## संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी अविलंब लागू करने की मांग

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में संशोधित लैंड पॉलिसी लागू करवाने के लिए जंतर मंतर पर रविवार को दिल्ली की 360 पंचायतों ने एक साथ मिलकर महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली के नोटिफाइड अर्बनाइजेबल जोन में अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना साकार करने के उद्देश्य से जमीन खरीदने वाली संस्था मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स ने भी हिस्सा लिया। साथ ही महापंचायत में वर्षों से अपने घर का सपना साकार का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों के हित में संशोधित लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को अविलंब लागू किया जाय। साथ ही जिन गावों में किसानों की जो जमीन है उस पर उन्हें निशुल्क मालिकाना हक दिया जाय। कार्यक्रम



में मौजूद मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी ऐंड लैंड ओनर्स के सदस्य केएस कृष्णन ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान 2001-2021 में अनुमान जताया गया था कि 2021 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच जायेगी। आनुमानित आबादी को मकान मुहैया कराने के लिए ही साल 2013 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर लैंड पूलिंग पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इस नीति में डीडीए को भूमि अधिग्रहण से दूर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली एजेंसी के तौर निर्धारित किया गया था।



पालम 360 खाप के वैनर तले रविवार को नई दिल्ली में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर पंचायत की।

फोटो: लेखराज

## मांगें पूरी न हुईं तो लोकसभा चुनाव में सिखाएंगे सबक

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** राजधानी के गांवों के अधिकारों और हाउस टैक्स, भवन उप नियम समेत विभिन्न टैक्स व नियम व कानून थोपने के खिलाफ पालम 360 खाप ने जंतर-मंतर पर रविवार को महापंचायत की।

महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान चौ. सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं करने वाली सरकारों को वह सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली सरकार व एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी जताई।

इस मौके पर चौ. सोलंकी ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर उपराज्यपाल ने उनसे बात की है और केंद्र सरकार से जुड़े मसलों पर भाजपा के नेताओं ने उनसे विचार विमर्श किया है, लेकिन दिल्ली सरकार व एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने उनके आंदोलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी अधिकतर मांगें दिल्ली सरकार व एमसीडी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक माह के अंदर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे लोग उनके घर के अंदर पंचायत करेंगे और वह किसी भी दिन उनके घर दस्तक दे सकते हैं।

कार्यक्रम में मौजूद मेम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ हाउसिंग सोसायटी

एंड लैंड ओनर्स के सदस्य केएस कृष्णन ने कहा कि डीडीए द्वारा तैयार दिल्ली के मास्टर प्लान 2001-2021 में अनुमान जताया गया था कि 2021 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस

आनुमानित आबादी को मकान मुहैया कराने के लिए ही साल 2013 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर लैंड पूलिंग पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इस नीति में डीडीए को भूमि अधिग्रहण से दूर रखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाली एजेंसी के तौर पर निर्धारित किया गया था। तब अनेक संस्थाओं ने सोसायटियां बनाकर किसानों से जमीन खरीदी लेकिन इससे पहले कि

सोसायटियां और उनके सदस्य अपने आशियाने का सपना पूरा कर पाते साल 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी में कई तरह के बदलाव कर दिये गए जिससे न सिर्फ सोसायटियों के सदस्यों बल्कि जमीन बेचने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महापंचायत में चौ. धारा सिंह प्रधान बवाना, चौ. नरेश प्रधान लाडोसराय, राव त्रिभुवन सिंह प्रधान सुरेंद्रहा, रणबीर प्रधान नरेला, सुरेश शौकीन प्रधान नांगलोई, बिजेन्द्र पहलवान, नारायण डगर वंडसा, भूषण त्यागी प्रधान बुराड़ी, रोहतास शौकीन प्रधान पीरागढ़ी आदि ने भी चेतावनी दी कि ग्रामीणों की अनदेखी करना बंद किया जाए।

**अधिकारों को लेकर 360 खाप पंचायत के प्रधान सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने किया ऐलान**

**महापंचायत में दिल्ली में संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करवाने पर हुई चर्चा**



लागू करो - लागू करो  
संशोधित लैंड यूजिंग पॉलिसी  
ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी  
मास्टर प्लान 2041 (दिल्ली)  
डी.डी.एड पर कार्यवाही शुरू करें  
लागू करो - लागू करो

लागू करो - लागू करो  
संशोधित लैंड यूजिंग पॉलिसी  
ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी  
मास्टर प्लान 2041 (दिल्ली)  
डी.डी.एड पर कार्यवाही शुरू करें  
लागू करो - लागू करो

लागू करो - लागू करो  
संशोधित लैंड यूजिंग पॉलिसी  
ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी  
मास्टर प्लान 2041 (दिल्ली)  
डी.डी.एड पर कार्यवाही शुरू करें  
लागू करो - लागू करो

लागू करो - लागू करो  
संशोधित लैंड यूजिंग पॉलिसी  
ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी  
मास्टर प्लान 2041 (दिल्ली)  
डी.डी.एड पर कार्यवाही शुरू करें  
लागू करो - लागू करो

लागू करो - लागू करो  
संशोधित लैंड यूजिंग पॉलिसी  
ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी  
मास्टर प्लान 2041 (दिल्ली)  
डी.डी.एड पर कार्यवाही शुरू करें  
लागू करो - लागू करो



**55**

**लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने को लेकर महापंचायत**

सुप्रीम

सेन

पितृभवन

बिजनेस

देश

22K